बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 157 ● नई दिल्ली ● सोमवार 06 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली के कई इलाकों में अगले 2 दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने बताई वजह

नई दिल्ली। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन के वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के कारण 6 और 7 अप्रैल को रोहिणी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी एवं कराला गांव के आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। टैंकर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोग आवश्यकता अनुसार टैंकर से पानी मंगवा सकते है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अनुसार 6 अप्रैल को सुल्तानपुरी क्षेत्र, मंगोलपुरी, रोहिणी सेक्टर-2 पॉकेट-4, फीलिंग पाइंट एवं कराला गांव और आसपास के इलाकों में पानी आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं, 7 अप्रैल को सुल्तानपुरी क्षेत्र, रोहिणी सेक्टर-3 पॉकेट-ए-1, सेक्टर-3 पॉकेट-बी 10, सेक्टर-3 पॉकेट-सी 12, सेक्टर-3 पॉकेट-एफ 23, फीलिंग पाइंट एवं कराला गांव के आसपास जल आपूर्ति बाधित होगी।

लोकसभा-विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी पर रार : केवल ध्यान भटकाने की चाल; कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

नई दिल्ली । कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि यह कदम बड़े और अधिक आबादी वाले रायों को लाभ पहुंचाएगा और यह कुछ और नहीं बल्कि जनता का ध्यान भटकाने का एक हथियार है। विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश की जनता को धोखा दे रहे हैं और भ्रामक बयान दे रहे हैं।

जनता का ध्यान भटकाने की चाल

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा प्रधानमंत्री अपने पुराने पैंतरे पर है, भ्रामक बयान दे रहे हैं जिनका मकसद धोखा देना है। वह कहते हैं कि यदि लोकसभा की ताकत 50त्र बढ़ाई जाती है और प्रत्येक राय की लोकसभा सीटों की संख्या भी 50त्र बढ़ाई जाती है, तो दक्षिण भारतीय रायों को कोई नुकसान नहीं होगा। रमेश ने आगे कहा यह देश की जनता को धोखा देना है, जिसमें प्रधानमंत्री को महारत हासिल है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश और केरल के बीच लोकसभा सीटों का अंतर अभी 60 है, जो मोदी के प्रस्ताव से बढ़कर 90 हो जाएगा। इसी तरह, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का अंतर 41 से बढ़कर कम से कम 61 हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा श्रीमान मोदी एक ऐसे प्रस्ताव को जबरन आगे बढ़ा रहे हैं जो बड़े और अधिक आबादी वाले रायों को अधिक लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि उनकी पहले से ही बड़ी संख्या और बढ़ जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि इसका असर सिर्फ

दक्षिण भारत पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर-पूर्व के रायों का भी सापेक्ष प्रभाव कम होगा। जयराम रमेश ने कहा राष्ट्र गंभीर आर्थिक और विदेश नीति संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री की एकमात्र चिंता लोकसभा और विधानसभाओं की ताकत बढ़ाने की है, वह भी बिना किसी सार्थक परामर्श और व्यापक सार्वजनिक बहस के। यह जनता का ध्यान भटकाने का एक हथियार है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक चुनावी रैली में कहा था कि बजट सत्र को तीन दिनों के लिए बढ़ाया गया है ताकि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को 2029 से लागू किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया था कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव से किसी भी राय, चाहे वह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना हो, में लोकसभा सीटों की संख्या में कमी नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2023 में पारित कानून के तहत लोकसभा और राय विधानसभाओं में महिलाओं को 33त्र आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लाभ 2029 के लोकसभा चुनावों से शुरू हो सकें और 33फीसदी महिलाएं संसद में बैठ सकें, इसके लिए अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से इस मुद्दे का समर्थन करने का आग्रह किया है, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस भी इस पर सहमति जताएगी।

राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी

कांग्रेस ने सरकार पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से संबंधित विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि यह आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। कांग्रेस ने परिसीमन अभ्यास में जल्दबाजी के गंभीर परिणाम होने की चेतावनी दी है। पार्टी ने कहा है कि वे वर्तमान अंतर और सापेक्ष शक्ति में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पारित होने के 30 महीने बाद तक सोती रही और अब चुनाव के मौसम में दोहरा श्रेय लेना चाहती है।

आप के लिए राघव चड्ढा का नया वीडियो- यह छोटा सा ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है; बोले- पंजाब मेरा घर है

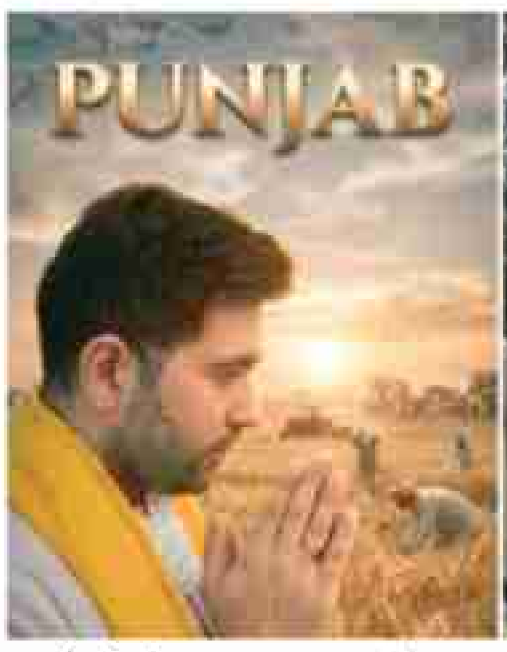

नई दिल्ली । राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा और पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आरोपों के जवाब राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर दे रहे हैं। रविवार को एक बार फिर राघव चड्ढा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह पंजाब के मुद्दों को सदन में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि, आम आदमी पार्टी (आप) के मेरे उन साथियों के लिए, जिन्हें यह कहते हुए वीडियो जारी करने पर मजबूर होना पड़ा कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दों को उठाने में विफल रहे, यह एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पंजाब मेरे लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। यह मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है। राघव चड्ढा ने शनिवार को अपनी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा और सुनियोजित अभियान का हिस्सा बताया। आप सांसद ने कहा कि वह संसद में आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाने जाता हूं, हंगामा करने और माइक तोड़ने नहीं। एक वीडियो संदेश में चड्ढा ने कहा, मैंने कभी विपक्ष के वॉकआउट में हिस्सा लेने से इन्कार नहीं किया और इस तरह के आरोप सफेद झूठ हैं। मैं आलोचकों को चुनौती देता हूं कि वे एक भी ऐसा उदाहरण बताएं जब मैंने विपक्ष के वॉकआउट में भाग नहीं लिया हो। संसद की पूरी कार्यवाही सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करने के आरोप पर चड्ढा ने कहा, पार्टी के किसी नेता ने मुझसे इस बारे में न तो औपचारिक और न ही अनौपचारिक रूप से संपर्क किया। मेरा ध्यान संसद में जीएसटी, आयकर, दिल्ली का प्रदूषण, पंजाब का पानी संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल यात्रियों की समस्याएं, मासिक धर्म स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई जैसे जनहित के मुद्दे उठाने पर रहा है। मैं संसद में आम आदमी के मुद्दे उठाने जाता हूं, हंगामा करने और माइक तोड़ने नहीं।

यमुना पर नया लोहा पुल तैयार, अब बाढ़ में भी नहीं रुकेगी ट्रेनों की रफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली में यमुना नदी पर बने ऐतिहासिक लोहे के पुल की जगह अब एक आधुनिक और ऊंचा पुल तैयार हो चुका है, जिससे रेल संचालन में बड़ी राहत मिलने वाली है. नए पुल के चालू होने के साथ ही यात्रियों को न सिर्फ सुरक्षित सफर मिलेगा बल्कि ट्रेनों की गति भी पहले से तेज होगी. उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे के अनुसार नया पुल पुराने पुल की तुलना में 4.5 मीटर ऊंचा बनाया गया है. यही वजह है कि यमुना का जलस्तर बढ़ने पर भी अब इस पुल से ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं होगा. पहले हर साल बाढ़ के दौरान रेल सेवा बाधित होने का खतरा बना रहता था, जो अब पूरी तरह खत्म हो गया है. करीब 150 साल पुराने लोहे के पुल की संरचना समय के साथ कमजोर हो चुकी थी. जलस्तर बढ़ते ही सुरक्षा के लिहाज से इस पर ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ता था. इतना ही नहीं, पुल की हालत को देखते हुए ट्रेनों को बेहद धीमी गति से गुजरना पड़ता था, जिससे यात्रियों को असुविधा होती थी और समय भी अधिक लगता था. दिल्ली और शाहदरा के बीच यमुना पर बना यह ऐतिहासिक 'लोहा पुल' अब सेवा से बाहर हो चुका है. कभी यह पुल उत्तर और पूर्व भारत को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण रेल कड़ी हुआ करता था. लाखों यात्रियों और भारी माल ढुलाई का भार उठाते-उठाते इसकी क्षमता कमजोर पड़ गई, जिसके बाद इसे बंद करने का फैसला लिया गया. 1866-67 में करीब 3,500 टन रॉट आयरन से तैयार यह पुल उस दौर

की इंजीनियरिंग का शानदार नमूना था. लगभग 1000 फीट लंबे इस पुल पर 1867 में पहली बार भाप इंजन ट्रेन चली थी, जिससे दिल्ली सीधे कोलकाता से जुड़ गया था. इसके बाद व्यापार, डाक व्यवस्था और सैन्य आवाजाही में क्रांतिकारी बदलाव आया था. इस पुल की डिजाइन भी बेहद खास थी. इसके ऊपरी हिस्से में रेलवे ट्रैक बिछे थे, जबकि निचले हिस्से का इस्तेमाल सड़क और पैदल मार्ग के रूप में किया जाता था. 1857 के बाद दिल्ली के पुनर्निर्माण और विस्तार में इस पुल की अहम भूमिका रही और यह आम लोगों के लिए यमुना पार करने का सबसे भरोसेमंद साधन बना रहा. नया पुल न केवल तकनीकी रूप से मजबूत है बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इससे रेल यातायात अधिक सुरक्षित, तेज और निर्बाध होगा, जो आने वाले समय में यात्रियों और माल परिवहन दोनों के लिए बड़ी राहत साबित होगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू की सक्षम यात्रा, स्टार्टअप्स को मिलेगा वित्तीय सहयोग और मेंटरशिप

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार, 5 अप्रैल 2026 को राजधानी से सक्षम यात्रा 2026 का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस विशेष पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर उभर रहे नए विचारों को पहचान देना और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देना है। झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करते समय मुख्यमंत्री ने युवाओं और नवोन्मेषकों का उत्साहवर्धन किया।

स्थानीय विचारों के लिए एक वैश्विक मंच

संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सक्षम यात्रा का मुख्य केंद्र दिल्ली है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा स्थानीय प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करेगी जहाँ उनके विचारों को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उन्हें फलने-फूलने के लिए आवश्यक

सहयोग और मार्गदर्शन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह पहल छोटे शहरों और समुदायों से निकलने वाले मौलिक विचारों को वास्तविक और बड़े प्रभाव में बदलने का काम करेगी।

समाधान और क्रियान्वयन के बीच की दूरी होगी कम

गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अक्सर बेहतरीन नवाचार केवल इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास सही मंच या क्रियान्वयन की योजना नहीं होती। उन्होंने कहा, ÷सक्षम यात्रा जैसी पहल नवाचार और उसके जमीनी स्तर पर लागू होने के बीच की खाई को पाटने का काम करती हैं।÷ यह यात्रा समुदाय-आधारित समाधानों को मुख्यधारा में लाने में सहायक सिद्ध होगी।

समावेशी विकास की ओर कदम

बता दें कि यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर उत्तर भारत के विभिन्न शहरों जैसे अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, आगरा और जयपुर से होते हुए वापस दिल्ली लौटेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ शिक्षाविद् अजय गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस पूरी यात्रा का उद्देश्य उन स्टार्टअप्स और नवाचारों को कामयाब ग्रांट्स जैसे कार्यक्रमों के जरिए मेंटरशिप और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं।

दिल्ली के सीमापुरी में 15 साल की नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत

नई दिल्ली । दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. 24 साल के युवक ने 15 साल की नाबालिग लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया. रविवार (5 अप्रैल) को इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई. राजधानी में अपराध के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला सीमापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां 24 वर्षीय जतिन ने 15 साल की नाबालिग लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. घटना शाम करीब सवा पांच बजे की बताई जा रही है, जो पीड़िता के घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर हुई. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक इस वारदात में कुछ और युवकों के शामिल होने की भी आशंका है. घायल नाबालिग ने हिम्मत दिखाते हुए खुद अपनी मां को फोन कर हमले की जानकारी दी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि नाबालिग ने हाल ही में 28 मार्च को अपना 15वां जन्मदिन मनाया था और 10वीं की परीक्षाएं भी दी थीं, लेकिन जिंदगी की शुरुआत ही उसके लिए आखिरी साबित हुई. रविवार (5 अप्रैल) सुबह करीब 5 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जतिन के नई सीमापुरी के सी-ब्लॉक स्थित घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई थी. इस घटना में उसकी मौत हो गई. उसका भाई आकाश जब मौके पर पहुंचा तो वह बुरी तरह झुलसा हुआ मिला था. जतिन ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था और पिता के निधन के बाद अपनी मां के साथ रह रहा था. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस हमले के पीछे असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई और भी शामिल था.

विध्वंस में बदलता सृजन

युद्ध विनाश का दूसरा नाम है जो बर्बरता और तबाही के अलावा कुछ नहीं लाता। युद्ध मानव द्वारा किए गए सृजन का विध्वंस करता है, विकास को पीछे धकेलता है और मानवता को पीछे धकेलता है। युद्ध में हमेशा आम जनता और निर्दोषों का नुकसान होता है। युद्ध में मृत खून से लथपथ लोगों की आत्माएं दर्द से कहराती हैं। धरती चीत्कार कर पुकारती है। हमें न युद्ध चाहिए और न हथियार, अहिंसा का मार्ग चाहिए, जिओ और जीने दो, मानव को मानव से शांति मार्ग चाहिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध 35वें दिन खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब यह पुलों, नागरिक ठिकानों, जल संशोधन केन्द्रों, रिफाइनरियों और गैस प्लांटों तक पहुंच गया है। अब यह जंग लोगों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की तरफ मुड़ चुका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में तेहरान और करज जैसे दो बड़े शहरों को जोड़ने वाला राजनीतिक बी-1 पुल को ध्वस्त कर दिया है। 400 मिलियन डॉलर की लागत से बना यह पुल केवल यातायात का जरिया नहीं था बल्कि ईरान की इंजीनियरिंग और उसकी मजबूती का प्रतीक था। इस पुल पर हमला करने का मकसद ईरान के लॉजिस्टिक को काटना है ताकि युद्ध की स्थिति में उसकी सेना को मूवमेंट करने में भारी परेशानी हो। ईरान ने भी अपना पुल ध्वस्त होने पर बदला लेने की कसम खाई है और ईरान ने खाड़ी और मध्यपूर्व के 8 पुलों की हिटलिस्ट जारी की है, जो उसके निशाने पर हैं। इसमें कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद ब्रिज, संयुक्त अरब अमीरात का शेख जायद ब्रिज, अलमक्ता ब्रिज और शेख खलीफा ब्रिज शामिल हैं। बहुमंजिला इमारतें और पुल गवाने में क्यों लग जाते हैं। अगर युद्ध में बुनियादी ढांचा ही तबाह हो गया तो फिर हाहाकार मचेगा और जनता त्राहि-त्राहि कर उठेगी। अब तक तनाव कम करने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ईरान द्वारा एक के बाद एक अमेरिकी लड़ाकू विमान और दो हैलीकाप्टरों को मार गिराए जाने के बाद पश्चिम एशिया में संकट और गहरा गया है। यद्यपि अमेरिका ने एक पायलट को बचा लेने का दावा किया है जबकि दूसरा पायलट लापता है। यदि लापता पायलट ईरान के हाथ लग जाता है तो अमेरिका की चिंताएं बढ़ जाएंगी। अमेरिका के करोड़ों रुपए के विमान तबाह होने से डोनॉल्ड ट्रम्प के उन दावों की पोल खुल गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल के तेल अबीब, यरूशलम, डिमोना और हाइफा जैसे शहरों को अपने रॉकेटों से निशाना बनाया है उससे इजराइल का सुरक्षा कवच माने गए आयरन डोम और लेजर बीम तकनीक भी नकारा साबित हुई। अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने भी ट्रम्प को बता दिया है कि ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी 55 प्रतिशत बरकरार है। यही कारण है कि ईरान अमेरिका के आगे झुकने से साफ इंकार कर रहा है। इजराइल के एयर डिफेंस को भेदने वाले ईरान के सस्ते और सटीक ड्रोन काफी कारगर साबित हुए हैं। इन ड्रोनों ने आधुनिक युद्ध और उसमें आर्थिक समीकरणों ने युद्ध का एक नया आयाम जोड़ दिया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ, अपने शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल पूरे पश्चिम एशिया में सैन्य ठिकानों, सैन्य ठिकानों, तेल-गैस के बुनियादी ढांचों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों को आक्रामक तरीके से निशाना बनाने के लिए किया है। पिछले एक महीने में खाड़ी क्षेत्र में फैली अराजकता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्धक्षेत्र में ड्रोन और वायु शक्ति की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यह सैन्य सिद्धांत, हर जगह अपनाया जा रहा है। शाहेद ड्रोन से हुआ भारी नुकसान इस बात को उजागर करता है कि कम लागत वाले कामिकाजे ड्रोन को बड़े पैमाने पर सैन्य हथियारों के जखीरे में शामिल करने का रणनीतिक फायदा कितना बड़ा हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दे दी है कि अब युद्ध के मैदान में ईरान का पलड़ा भारी है और ट्रम्प बुरी तरह से उलझ गए हैं। उन्हें युद्ध से बाहर निकलने के लिए कोई पतली गली नहीं मिल रही। ट्रम्प ने राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि युद्ध अंततः उनके फायदे के लिए है लेकिन अमेरिकी जनता ने उससे असहमति जता दी है। जंग के बीच ट्रम्प ने आर्मी चीफ समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया। जंग के बीच घोड़ों का बदलना इस बात का प्रमाण है कि उन्हें युद्ध में वांछित परिणाम नहीं मिल रहे। ट्रम्प के मित्र रहे देश भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। अमेरिका नाटो की सुरक्षा छतरी के तले पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के साथ 77 साल पुरानी साझेदारी तोड़ने को तैयार नजर आ रहा है। खासकर, अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस बयान के बाद कि वह इस गठबंधन से (जो उनकी नजर में एक -कागजी शेर-है) निकलने पर 'बिल्कुल' विचार कर रहे हैं। ट्रम्प की यह और ऐसी ही अन्य टिप्पणियां व्हाइट हाउस की उस साफ जाहिर निराशा के बाद आयी हैं कि यूरोपीय और अन्य सहयोगियों ने ईरान के खिलाफ युद्ध अभियान में अमेरिका और इजराइल के सहयोग के लिए सैन्य संसाधनों को मौके पर नहीं भेजा। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य, जो अभी तेहरान के नियंत्रण में है, से तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए। ट्रम्प ने बार-बार शिकायत की है कि वाशिंगटन को नाटो से उतना लाभ नहीं मिल रहा, जितना वह उसमें लगा रहा है। हाल ही में उन्होंने मीडिया से कहा, यह एक तरफ जाने वाली सड़क है। उन्होंने अपनी एक हालिया टिप्पणी से यह भी संकेत दिया है कि नाटो शायद निष्प्रभावी वैश्विक ताकत बन गया है। उनकी टिप्पणी थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं कि नाटो में अपने सदस्यों की रक्षा करने का दम नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को की सैन्य आक्रामकता और संभवतः आगे चलकर बाल्टिक राष्ट्र क्षेत्र में उसके सैन्य दुस्साहस के संदर्भ में यह टिप्पणी अतिरिक्त महत्व की हो जाती है। दुनिया में तेल और ऊर्जा का संकट पहले ही खड़ा हो चुका है। ट्रम्प अपना लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रहे हैं। अगर युद्ध लम्बा खिंचता है तो तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होगी। लोगों पर मंदी और महंगाई की दोहरी मार पड़ेगी। युद्ध रुकने के बावजूद ईरान और खाड़ी देशों को दोबारा से बुनियादी ढांचे के निर्माण? और आर्थिक संकट से उभरने में वर्षों लग जाएंगे। युद्ध विरोधी ताकतों को एकजुट होकर ईरान से संवाद का रास्ता कायम कर युद्ध रोकने के गम्भीर प्रयास करने होंगे, अन्यथा एक सिरफिरे की सनक का खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी।

बुजुर्गों के आंसू पोंछने की प्रेरणादायी पहल

ओल्ड इज गोल्ड कहना बहुत आसान है परन्तु बुजुर्गों को सोना मान कर उनका सम्मान करने वाली युवा पीढ़ी इसे निभाती कहां है? बुजुर्ग घरों में अकेले हैं। संतान का कैरियर बनाने के लिए अपनी जिन्दगी दांव पर लगाने वाले मां-बाप को बुढ़ापे में संतान बड़े-बड़े पद पाकर ठुकराने लगती है तो वरिष्ठ नागरिक केसरी वल्लभ जैसे मंच समाज में उभरते हैं जो बुजुर्गों के सम्मान को सुरक्षित रखने का धर्म निभाते हैं। क्योंकि मैं इसकी चेयरपर्सन हूं, पिछले दिनों तेलंगाना सरकार ने बुजुर्ग मां-बाप के आंसु पोंछने वाला कानून बनाया तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि अब राज्य सरकार भी इस दिशा में पग उठाने लगी है।

बच्चे जब बड़े होकर कैरियर बनाने के लिए घर-बार छोड़कर मां-बाप को अकेला छोड़ देते हैं तो बुजुर्गों का जीवन सिसकियों से भरने लगता है। इन घटनाओं को सामने रखकर तेलंगाना विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत व्यवस्था यह है कि अगर कोई समाज में माता-पिता की उपेक्षा करता है तो उनके वेतन में से धन काट कर बुजुर्ग माता-पिता को दिए जाने की व्यवस्था है। मैं इस पहल का स्वागत करती हूं। बुजुर्ग माता-पिता के आंसू पोंछने का यह पहला स्वागत योग्य कदम है। जहां बुजुर्गों को भगवान मान कर पूजा जाता है और जहां संतान के श्रवण कुमार बनने के साक्ष्य भी रहे हों तो उस देश में बुजुर्गों की उपेक्षा क्यों है। लेकिन यह बात अच्छी है कि सरकारें इस दिशा में उनके आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। बुजुर्गों की इस घर-घर, शहर-शहर, देश और विदेश तक फैली गंभीर समस्या के निदान और अपनों द्वारा की जा रही उपेक्षा पर कुछ करने का सही वक्त आ गया है। देश में बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। गांवों से शहरों की ओर पलायन, संयुक्त परिवारों का टूटना और तेजी से बदलती जीवनशैली के कारण बुजुर्गों की देखभाल नहीं करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई दफा माता-पिता को उम्र के आखिरी पड़ाव पर या तो अकेले रहना पड़ता है या फिर किसी वृद्धाश्रम की शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। मेरा मानना है कि भारतीय समाज में बुजुर्गों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव जैसी परंपराएं हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का आधार रही हैं, लेकिन आधुनिक जीवनशैली, शहरीकरण और संयुक्त परिवारों के टूटने के कारण आज बुजुर्गों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इसी संदर्भ में हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा लिया गया निर्णय एक महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी कदम के रूप में सामने आया है। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता सहायता निगरानी विधेयक, 2026 पारित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस विधेयक के तहत सरकारी, निजी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है तो उसके वेतन से 15 प्रतिशत या रुपए 10,000 (जो भी कम हो) काटकर माता-पिता को दिया जाएगा। इतना ही नहीं धन के न मिलने पर बुजुर्ग माता-पिता शिकायत कर सकते हैं और प्रशासन 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करेगा। मां-बाप को अपनी जिंदगी बसर करने के लिए कानून की मदद लेनी पड़ रही है। हालांकि केन्द्र व राज्य सरकारें इस मामले में कानून पहले ही लागू कर चुकी हैं लेकिन फिर भी बुजुर्गों की उपेक्षा एक आम बात बन चुकी है। यद्यपि बुजुर्ग माता-पिता के लिए पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 लागू है, पर सोशल मीडिया लगातार कहता आ रहा है कि इसका असर जमीन पर दिखाई नहीं देता। यह कानून 2007 के केंद्रीय कानून से आगे बढ़कर अधिक सख्त और प्रभावी व्यवस्था प्रदान करता है। हमारे देश में यह अपनी तरह का पहला और अनूठा प्रयास माना जा रहा है, जिसमें पारिवारिक जिम्मेदारी को कानूनी रूप दिया गया है। तेलंगाना सरकार का यह कदम केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार का प्रयास भी है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, आज के समय में कई लोग अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने माता-पिता की उपेक्षा करने लगते हैं। यह कानून लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह सच है कि यादातर बुजुर्ग आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। इस कानून के माध्यम से उन्हें नियमित आर्थिक सहायता सुनिश्चित होगी। जहां पहले माता-पिता की सेवा केवल नैतिक कर्तव्य थी, अब इसे कानूनी दायित्व भी बना दिया गया है। इससे समाज में अनुशासन बढ़ेगा। तेलंगाना का यह निर्णय अन्य राज्यों के साथ-साथ न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में एक उदाहरण बन सकता है।

सम्पादकीय...

मानसिक स्वास्थ्य की पुकार

बेंगलुरु, जिसे भारत की आई.टी. राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, पिछले दिनों एक ऐसी घटना से हिल गया, जो न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। गत 31 मार्च को कोठनूर इलाके के एक हाई-राइज अपार्टमेंट में एक युवा तकनीकी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। पति भानुचंद रेड्डी (32) और पत्नी बीबी शाजिया सिराज (31), दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों की कमाई लाखों में, अमरीका में काम का अनुभव, 80 लाख का सालाना पैकेज और सफलता की सारी बाहरी निशानियां। लेकिन अंदर से, नौकरी खोने का भय और बढ़ता तनाव। ठीक उसी दिन, जब वैश्विक स्तर पर ए.आई. की वजह से आई.टी. सैक्टर में भारी छंटनी की खबरें आ रही थीं, भानुचंद अमरीका में काम कर रहे थे। ए.आई. टूल्स के कारण उनकी टीम में छंटनी हुई और उनकी नौकरी चली गई। भारत लौटकर वह नई नौकरी की तलाश में लगे लेकिन असफल रहे। [illegible] ने उन्हें घेर लिया। स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने यही लिखा, ''नौकरी की अनिश्चितता और लगातार दबाव।'' पत्नी शाजिया आई.बी.एम. में नाइट शिफ्ट कर रही थीं। सुबह 7.30 बजे घर लौटीं तो पति का कमरा अंदर से बंद था। सुरक्षा गार्ड ने दरवाजा तोड़ा तो भानुचंद फांसी पर लटक रहे थे। शाजिया ने 20 मिनट तक वह दृश्य देखा। फिर वह अचानक 18वें फ्लोर पर पहुंचीं और वहां से नीचे कूद गईं। यह घटना ए.आई. क्रांति की उस काली साइड की प्रतीक है, जो कल तक 'भविष्य की तकनीक' मानी जा रही थी। ठीक उसी दिन, 31 मार्च 2026 को, अमरीकी सॉफ्टवेयर दिग्गज ऑरेकल ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी ए.आई. डाटा सैंटर बनाने के लिए भारी निवेश कर रही है। 2026 में 500 करोड़ डॉलर से यादा का कैपिटल निवेश भी किया। लेकिन इस खर्च को पूरा करने के लिए उसने लागत घटाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 20,000-30,000 तक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। ऑरेकल अकेली नहीं। 2026 में ए.आई. की वजह से बिग टैक की छंटनी की लहर चल रही है। अमेजन ने जनवरी में 16,000 कॉर्पोरेट जॉब्स काटे। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल 15,000 पद घटाए। मेटा, एटलासियन, ब्लॉक आदि सभी कंपनियां ए.आई. के नाम पर कर्मचारियों को 'रिडंडेंट' बता रही हैं। भारत में भी आई.टी. सैक्टर में 2017 से अब तक 227 से यादा सुसाइड केस दर्ज हुए हैं। एन.सी.आर.बी. के 2023 के आंकड़ों के अनुसार कुल 1,71,418 आत्महत्याएं हुईं, जिनमें युवा प्रोफेशनल्स (25-40 साल) की संख्या सबसे यादा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे हर शहर में ए.आई. छंटनी का डर युवाओं को घेर रहा है। समस्या सिर्फ नौकरी चले जाने की नहीं, समस्या उस चिंता की भी है, जो ए.आई. के नाम पर पैदा हो रही है। ए.आई. टूल्स कोडिंग, डाटा एनालिसिस, यहां तक कि सॉफ्टवेयर डिजाइन में इंसानों से बेहतर साबित हो रहे हैं। कंपनियां सोच रही हैं कि 'कम लोगों से यादा काम'। लेकिन कर्मचारी?

पश्चिम बंगाल में बढ़ती अराजकता लोकतंत्र के लिए चुनौती

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिस तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या

निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुनः स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।

विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब वही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकता—तीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें। निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुनः स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।

सम्राट के नाम पर नीतीश का रूप विराट

सन्निपात मार गए बिहार के सियासी हालात और इतने गुमसुम सी इतनी उदास हुई खामोशियों में से अपना गुजरा हुआ चमकता अतीत ढूंढने में इस बिहारी महारथी को शायद थोड़ा वक्त लगे, पर लगता नहीं है कि कल के सुशासन बाबू ने आज के भगवा आभामंडल के समक्ष पूरी तरह अपने घुटने टेक दिए हैं। उनकी वाचाल भाव भंगिमाओं और किंचित अस्थिर मनोदशा को आधार बना उन्हें बिहार से चलता करने की रणनीति बुनने वाले महारथीगण भी समझ गए हैं कि फिलवक्त सियासी रण में यह योद्धा भले ही कितना थका हुआ और बेदम दिख रहा हो, पर यह अभी हारा नहीं है, पलटवार के लिए उसने ही मुस्तैदी से कमर कस रखा है। बुधवार को जैसे ही भाजपा के एक बड़े नेता ने अपने सबसे परम शिष्य सम्राट चौधरी से राजतिलक के लिए मुफीद घड़ी को कहा, नीतीश अपनी ओढ़ी हुई स्थितप्रज्ञता से बाहर आ गए। उनकी असहमतियों ने भी फौरन आकार लेने शुरू कर दिए। सूत्रों की मानें तो सम्राट के गद्दी की ओर प्रस्थान करने से कहीं पहले ही नीतीश ने अपने विरोध के स्वर मुखर कर दिए। सूत्र यह भी बताते हैं कि नीतीश ने सीधे एक अन्य भाजपा नेता से बात करने की जिद ठान ली, यह बात हुई भी और नीतीश ने उनके समक्ष खुलकर अपने मन के उद्गार व्यक्त कर दिए। नीतीश की जोर मूलतः तीन बातों पर था, एक-बिहार का अगला सीएम उनकी सहमति से बनना चाहिए, दो-नए सियासी हालात में नया विधानसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी यानी जदयू से ही होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गृह मंत्रालय का महकमा भी जदयू के पास ही रहना चाहिए। सम्राट चौधरी के नाम की वकालत करने वाले भगवा रणनीतिकारों के अपने तर्क हैं। इनका कहना है कि 'सम्राट जिस कोइरी जाति से आते हैं, यह जाति उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी प्रभावी है, सो 27 के आने वाले यूपी चुनाव में भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है।' दूसरी बात जो सम्राट के समर्थन में कही जा रही है कि वे काम करने वाले दबंग छवि के नेता हैं, बिहार में तेजस्वी यादव को बस वही काउंटर कर सकते हैं। वैसे तो सम्राट का नीतीश के बेटे निशांत कुमार से भी काफी याराना है, इन दिनों नीतीश के करीबी निशांत को नीतीश के असली वारिस के तौर पर तैयार करने की मशक्कत में जुटे हैं। कहते हैं स्वयं भाजपा के उक्त बड़े नेता भी नीतीश की इन बातों से इत्तफाक रखते हैं कि बिहार में नीतीश का चाहे जो भी उत्तराधिकारी चुना जाए वह साफ-सुथरी छवि का होना चाहिए, जिनमें नीतीश के वोट भाजपा को ट्रांसफर कराने की कूवत भी हो। फिलहाल बिहार में नीतीश के उत्तराधिकारी का मामला नए पेंचोखम में उलझ गया लगता है।

अकालियों का साथ क्यों छूटा- एक वक्त तो इस बात के साफ संकेत मिल रहे थे कि इस दफे के आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का चुनावी गठबंधन तय है, दोनों पार्टियां मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगी। पहले सुखबीर बादल फिर हरसिमरत कौर बादल की मुलाकात भी भाजपा के बड़े नेता से हो गई और गठबंधन के फार्मूले पर बातें भी होने लगी। इसके बाद भाजपा ने दिल्ली सरकार में अपने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में एक टीम बनाई और इस टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे पंजाब की सभी 117 सीटों की जमीनी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए गहन विश्लेषण की बानगी भाजपा आला कमान के समक्ष प्रस्तुत करें। इससे पहले भाजपा ने इन सभी 117 सीटों को लेकर आईबी से एक रिपोर्ट पहले ही तलब कर रखी थी। दोनों रिपोर्ट्स के [illegible] अकाली दल का [illegible] कोर वोट बैंक (जट सिख) भाजपा को ट्रांसफर नहीं हो पाते। बल्कि जहां अकाली दल की जगह भाजपा का उम्मीदवार मैदान में होता है, वे सिख वोट या तो आप को या फिर कांग्रेस में चले जाते हैं। वैसे भी पंजाब [illegible] (यानी [illegible] खत्री जाति) हैं, सिरसा स्वयं एक [illegible] खत्री सिख हैं, पार्टी के पास अब भी कोई जनाधार वाला जट सिक्ख नेता नहीं है जो वे वोट भाजपा के पाले में ला सके। सो, भाजपा रणनीतिकारों ने हरियाणा चुनाव का फार्मूला पंजाब में आजमाने का निर्णय लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान दक्षिण हरियाणा की यादातर सीटों पर जहां भाजपा कमजोर दिख रही थी, वहां संघ व भाजपा कैडर ने पूर्वांचल वोटर (बिहार/यूपी) पर खूब जोर लगाया था। महज इन वोटरों के बदौलत ही वहां मैदान मार लिया गया। पंजाब में भी 50 से यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं (खास कर लुधियाना, जालंधर व चंडीगढ़) जहां 30-60 फीसदी तक पूर्वांचल वोटर्स हैं, सो इस बार भी भाजपा रणनीतिकार इन्हीं पूर्वांचल मतदाताओं पर दांव लगाना चाहते हैं। भाजपा की कोशिश है कि 'अगर वह इस दफे के चुनाव में 'ठीक-ठाक' सीटें जीत लेती है तो फिर वह अकालियों को सरकार बनाने के लिए उनके साथ 'पोस्ट पोल' गठबंधन कर सकती है और सरकार में रोटेशन के आधार पर अपना सीएम भी मांग सकती है।'

कब होगा प्रियंका के मन का- प्रियंका चतुर्वेदी अभी-अभी तो उपरी सदन से रिटायर हुई हैं, पर सदन में अपनी पुनर्वापसी के लिए फिर से उन्होंने कमर कस ली है। राज्यसभा से विदाई के बाद कम से कम उन्होंने पांच पार्टियां दीं, [illegible] पार्लियामेंट के अपने साथियों के लिए। इन तमाम पार्टियों का एजेंडा बस एक ही था कि प्रियंका के नाम का [illegible] की भी चर्चा होती रहनी चाहिए। पर अब सवाल सबसे अहम है कि उन्हें वापिस राज्यसभा में लेकर आए कौन? बिचारे आदित्य ठाकरे करें भी तो क्या, शिवसेना उद्धव इस दफे तो जरूरी गिनती बल के करीब भी नहीं थी। कहते हैं प्रियंका ने देवेंद्र फड़णवीस के भी खूब चक्कर लगाए, पर बात वहां भी नहीं बनी। फिर उन्होंने एकनाथ शिंदे का रुख कर लिया, पर एकनाथ के पास भी इस बार उन्हें उपकृत करने के जल्दी उपक्रम नहीं थे, तो जया बच्चन के मार्फत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को पकड़ लिया। जया बच्चन स्वयं प्रियंका की पैरवी लेकर अखिलेश के पास जा पहुंचीं। कहते हैं अखिलेश ने छूटते ही जया से कह दिया 'आपकी बात कुछ और है, हमारा परिवार आपकी बहुत इज्जत करता है, पर हमारे लिए इनकी (प्रियंका की) उपयोगिता क्या है। वैसे भी हम अपनी पार्टी से केवल बाहरियों को कब तक सदन में भेजते रहेंगे इससे हमारी पार्टी कैडर में भी गलत संदेश जाता है।' भले ही प्रियंका चतुर्वेदी के लिए फिलवक्त सारे सियासी रास्ते बंद लग रहे हों, पर नया रास्ता ढूंढ निकालने में तो उन्हें महारथ हासिल है।

रंग नहीं लाई केसी की कोशिश- केसी त्यागी की शुरू से यही इच्छा थी कि अगर एक बार वे जदयू को अलविदा कहें तो फिर सीधे सपा की ट्रेन पकड़ लें। यही वजह है कि जदयू को आधिकारिक रूप से अलविदा कहने से पहले ही वे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिल रहे थे। पर शायद अखिलेश उन्हें पार्टी में लेने के लिए इतने उत्साही नहीं लग रहे थे, उन्हें नहीं लग रहा था कि केसी के पार्टी में आने से सपा को इसका कोई खास लाभ होने वाला है। दूसरा उन्हें यह भी लग रहा था कि केसी एक फेंक-फकाए राजनेता हैं, सपा में आने की एवज में वे उससे जरूर कुछ बड़ा पाने की आस लगाएंगे। सो, अखिलेश ने यह कार्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव के हवाले कर दिया कि 'वे केसी त्यागी से बात कर उनका मन टटोलें कि आखिरकार वे चाहते क्या हैं?' इसके बाद भी केसी त्यागी कोई दो दफे प्रोफेसर साहब से मिलने उनके घर गए, हर बार रामगोपाल का यही रटा-रटाया जुमला होता रहा कि 'आइए आपका सपा में दिल से स्वागत है।' पर उन्होंने कभी इस बात का खुलासा ही नहीं किया कि वे बदले में क्या 'डील ऑफर' कर रहे हैं। जब केसी को लगा कि प्रोफेसर साहब टाल-मटोल कर रहे हैं, ऑफर करने के लिए उनके पास कुछ भी ठोस नहीं तो वे वहां से सीधे जयंत चौधरी के पास चले गए। जयंत चौधरी किंचित यादा समझदार निकले, उन्होंने बातचीत की शुरुआत में ही केसी त्यागी को कह दिया कि 'वे केसी के पुत्र को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में रालोद के टिकट पर मुजफ्फरनगर से चुनावी मैदान में उतारेंगे। सो, एक पिता ने अपने पुत्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस प्रस्ताव पर सहर्ष अपनी सहमति दे दी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/30882)

विश्वसनीयता का पैमाना हैं अखबारों की खबरें - सूर्यप्रताप शाही

कुशीनगर ।

प्रदेश सरकार के कृषि एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि बदलते समय में पत्रकारिता के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और डिजिटल युग के आगमन के साथ नई चुनौतियां भी सामने आई है। इसके बावजूद आज भी अखबारों की खबरों को विश्वसनीयता का प्रमुख पैमाना माना जाता है। उन्होंने पत्रकारों से अपेक्षा की कि समाचारों को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यपरक एवं जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दें। शाही पडरौना स्थित एक निजी होटल में आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। इतिहास में पं. मदन मोहन मालवीय एवं रामनाथ गोयनका जैसे पत्रकारिता के पुरोधाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनी रही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण

पूर्ण सत्य का उद्घाटन पत्रकारों का दायित्व-शशांक मणि चुनौतीपूर्ण है ग्रामीण क्षेत्रों की पत्रकारिता-विजय दुबे

पत्रकारों की समस्याओं एवं चुनौतियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराते हुए उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों से अपील की कि निजी वार्तालाप को समाचार का हिस्सा बनाकर किसी की निजता का उल्लंघन न किया जाए। देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकारों का दायित्व है कि वे अर्धसत्य से बचते हुए पूर्ण सत्य को समाज के सामने प्रस्तुत करें तथा सकारात्मक अभियानों में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है तथा ग्रामीण पत्रकारों के हितों एवं संघर्षों में उनका निरंतर सहयोग रहेगा। कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) राजेश्वर सिंह, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूल बदन कुशवाहा, विधायक हाटा मोहन वर्मा, विधायक सदर मनीष जायसवाल, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडेय, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोंड, भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं वक्ताओं ने भी संबोधित किया। सम्मेलन के संयोजक एवं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार उपाध्याय ने स्वागत भाषण देते हुए अतिथियों का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया। इस अवसर पर संगठन की ओर से मुख्य अतिथि को सात सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। कार्यक्रम का संचालन यूएन इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अनूप कुमार मिश्र ने किया। कार्यक्रम में महेंद्र नाथ सिंह, कैप्टन वीरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश द्विवेदी, मारकंडे शाही, विंध्यवासिनी श्रीवास्तव, डॉ अरुण कुमार गौतम, शैलेंद्र शुक्ला, डॉ वैभव योति श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन पांडे, फरेंद्र पांडे, हरिशंकर चौबे, संजय पांडे, नत्थू शर्मा, अजीत यादव, प्रभु नंद उपाध्याय सहित अनेक पदाधिकारी, पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

दो मंजिला मकान से गिरकर मजदूर की दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

पत्नी की पहले ही हो चुकी थी मौत, दो मासूम बचों के सिर से उठा पिता का साया

भटनी देवरिया।

भटनी क्षेत्र के बभनौली गांव निवासी एक मजदूर की काम के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जितेंद्र यादव सकरापार गांव में जगन्नाथ तिवारी के यहां मजदूरी का काम कर रहे थे। इसी दौरान दो मंजिला मकान पर काम करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक जितेंद्र यादव के परिवार पर पहले से ही दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। उनकी पत्नी का कुछ दिन पहले ही निधन हो चुका था। उनके पीछे 14 वर्ष और 12 वर्ष के दो मासूम बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। जितेंद्र तीन भाइयों में एक थे।घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना के बाद सूचना मिलते ही मृतक मजदूर के घर पुलिस ने पहुँच कर घटना के सम्बंध में जानकारी ली।

किशोरी की निर्मम हत्या, चाकू से गोदकर गला रेता, पुलिस ने पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया

देवरिया।

जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत नौतन हथियागढ़ गांव में शनिवार की रात एक 16 वर्षीय किशोरी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। पुलिस ने रात में ही पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव की रहने वाली अंजली (16) पुत्री मलका प्रसाद शनिवार रात करीब आठ बजे अपनी बड़ी बहन गुड़िया और छोटे भाई अनीश के साथ सहोदर पट्टी चौराहा पर मोबाइल ठीक कराने जा रही थी। चौराहे से कुछ दूर पहले ही बाइक सवार तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने तीनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक

युवक ने चाकू निकाल लिया, जिसे देखकर तीनों जान बचाने के लिए भागने लगे। आरोपियों ने उनका पीछा करते हुए गेहूं के खेत में अंजली को पकड़ लिया। पहले पीछे से गर्दन पर दो चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वह खेत में गिरकर तड़पने लगी। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुके। अंजली को जीवित देखकर वे दोबारा लौटे और उसका गला

किशोरी अपनी बहन व भाई के साथ मोबाइल ठीक कराने जा रही थी, रास्ते में बाइक सवार तीन युवकों ने रोका

रेतकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या के पीछे कुछ माह पहले गांव के एक परिवार से हुए मारपीट और पुरानी रंजिश होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और रात लगभग दो बजे गांव सहित आसपास के इलाकों से पांच संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शिक्षकों का धरना 10 अप्रैल को

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की 29 मार्च 2026 को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रांतीय एवं मंडलीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी चेतनारायण सिंह, संरक्षक एमएलसी राजबहादुर सिंह चंदेल तथा महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मंडलीय एवं जनपदीय स्तर पर शिक्षकों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण न होने पर चिंता व्यक्त की गई। निर्णय लिया गया कि 10 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:00 बजे से 4:00 बजे तक संगठन पदाधिकारी एवं शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान समस्याओं के समाधान के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जनपद के सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं से अपील की गई है कि वे समय से धरना स्थल पर पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो सके। यह जानकारी जिला अध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया एवं जिला मंत्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से दी।

रील बनाने की सनक...जान जोखिम में डालकर वीडियो शूट करता दिखा बुजुर्ग

वीडियो वायरल होते ही शुरू बुजुर्ग की शुरू हुई आलोचना

महराजगंज।

जिले में इन दिनों युवाओं के साथ ही बुजुर्गों पर भी वायरल होने का जुनून सवार है। क्योंकि वह सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। इसके लिए इन्हें जान ही जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। रील बनाने के दौरान हादसे के कई मामले भी सामने आ चुके है। लेकिन उसके बाद भी रील बनाने वाले युवाओं के साथ बुजुर्गों की आँखें नहीं खुल रही हैं। यही कारण है कि वो बगैर किसी परिणाम सोचे ही खतरनाक स्टंट कर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे है। हालांकि इस वायरल वीडियो को ख्वाजा एक्सप्रेस पुष्टि नहीं कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में एक बाइक पर बुजुर्ग खतरनाक स्टंट करता दिख रहा है। वह बाइक की दोनों हैंडल को छोड़ चला रहा है। इतना ही नहीं वह बाइक पर खड़ा होकर चश्मा लगाते निकालते दिख रखा है। बुजुर्ग की खतरनाक स्टंट को देख लोग कमेंट भी कर रहे है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों की गुस्सा फूटा पड़ा। उन लोगों ने सोशल मीडिया के लिए इस तरह का स्टंटबाजी पर नाराजगी जाहिर कर रहे है। इसके साथ ही सड़क पर ऐसा करने वाले शख्स को चिन्हित कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक शख्स ने लिखा है कि सड़क पर यातायात नियमों का उलंघन करने के साथ ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

वही एक दूसरे शख्स ने कमेंट में लिखा है कि अगर स्टंट करने में इतना अच्छा है, तो कोई प्राइवेट जगह खरीद लेनी चाहिए। सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर खतरनाक स्टंट करने वाले के खिलाफ पुलिस को सख्ती करना चाहिए। वही पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

पीएलवी रामाश्रय पांडेय की पहल से साथ रहने पर सहमत हुए पति-पत्नी

- मध्यस्थता से दूर हुआ मनमुटाव, दोनों पक्षों ने रजामंदी जताई -वपुलिस व विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से परिवार में लौटी खुशियां

पटहेरवा कुशीनगर ।

मनमुटाव के चलते अलग रह रहे दंपती को एक बार फिर साथ लाने में पैरा लीगल वालेंटियर एडवोकेट रामाश्रय पांडेय की मध्यस्थता निर्णायक साबित हुई। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा मनमुटाव सुलझ गया व आपसी सहमति से साथ रहने का निर्णय लिया गया। छहूं निवासी मोतीलाल की पुत्री पार्वती का विवाह कसया थाना क्षेत्र के सपहा निवासी मुकेश के साथ हुआ था। कुछ समय बाद आपसी मतभेद बढ़ने पर पार्वती अपने मायके में रहने लगी थी। इस बीच मुकेश ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद समाधान की प्रक्रिया शुरू हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पैरा लीगल वालेंटियर रामाश्रय पांडेय ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत कराई। समझाने व कानूनी पहलुओं की जानकारी देने के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी व दंपती ने पुनः साथ रहने का निर्णय लिया। एडवोकेट रामाश्रय पांडेय ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य ऐसे पारिवारिक विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, जिससे न्यायालयों पर भार कम हो व परिवारों में सौहार्द बना रहे। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में पुलिस का प्रयास रहता है कि पहले आपसी सुलह से समाधान कराया जाए, ताकि परिवार टूटने से बच सकें व समाज में सकारात्मक संदेश जाए। इस दौरान एसआई संतोष कुमार, विनायक यादव, अंकित, हेड कांस्टेबिल श्यामजनम यादव, बीपीओ जितेंद्र कुमार, प्रदीप मौर्य, महिला कांस्टेबिल ममता आदि मौजूद रहे।

गहराते एलपीजी संकट से धुएं में घुटती रोजी-रोटी, झुग्गी वाले ज्यादा परेशान; सरकार का दावा- सब ठीक

नई दिल्ली । दिल्ली में गहराते गैस संकट ने अब छोटे ढाबों और रेहड़ी-पटरी पर खाना बेचने वालों की रोजी-रोटी पर सीधा असर डाला है। पहले जहां एलपीजी सिलेंडर की नीली लौ पर दाल-रोटी पकती थी, वहां लकड़ी और कोयले के चूल्हे जल रहे हैं। धुएं के बीच खाना बनाना मजबूरी बन गया है और बढ़ती लागत ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। आउटर रिंग रोड सीमापुरी में सड़क किनारे ढाबा चलाने वाले बृजेश ने बताया कि पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा है। एजेंसी जाने पर स्टॉक खत्म होने की बात कही जाती है। मजबूरी में लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ रहा है। पहले एक सिलेंडर में कई दिन काम चलता था लेकिन अब रोज लकड़ी खरीदनी पड़ती है जिससे खर्च बढ़ा और मुनाफा घटा है। भजनपुरा में ठेला लगाकर खाना बेचने वाले सोनू ने कहा कि बाजार में गैस ब्लैक में मिल रही है जिसकी कीमत 3000 से ज्यादा है। जो छोटे दुकानदारों के लिए बहुत महंगा है। सिलेंडर खरीदने पर खाने का रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो हर कोई ग्राहक नहीं दे पाएगा। ऐसे में लकड़ी और कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है। धुएं में काम करने से आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होती है। सीलमपुर के ढाबा संचालक मो. रशीद का कहना है कि गैस कमी का असर ग्राहकों की संख्या पर भी पड़ा है। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनने में समय ज्यादा लगता है, ग्राहक इंतजार नहीं कर पाते और दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। अब आधी कमाई भी मुश्किल हो गई है। करावल नगर में चाय और पराठा बेचने वाले आलोक तिवारी बताते हैं कि गैस संकट ने छोटे ढाबों को पुराने दौर में धकेल दिया है। लकड़ी के चूल्हे पर काम करना मुश्किल है, साथ ही धुएं और गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। अगर जल्द गैस आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो छोटे ढाबे बंद हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस संकट का सबसे ज्यादा असर गरीब और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। बड़े होटल और रेस्टोरेंट किसी तरह सिलेंडर का इंतजाम कर लेते हैं लेकिन छोटे ढाबे वालों के पास सीमित संसाधन हैं। ऐसे में प्रशासन और आपूर्ति विभाग से गैस की नियमित आपूर्ति करने की मांग तेज हो गई है। राजधानी में एलपीजी की आपूर्ति में कमी ने दिहाड़ी मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। गैस एजेंसियों पर बड़े सिलिंडरों के लिए लंबी कतारें लगी हैं, वहीं छोटे सिलिंडर भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में छोटे सिलिंडरों पर निर्भर मजदूरों को गैस के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। कई इलाकों में गैस भरने वाली दुकानें बंद पड़ी हैं और जहां पहले भीड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़े सिलिंडरों के साथ साथ छोटे सिलिंडरों की कमी भी लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। कम खपत वाले परिवारों और छोटे कारोबारियों को खासतौर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई एजेंसियों पर छोटे सिलिंडर या तो उपलब्ध नहीं हैं या बेहद सीमित संख्या में मिल रहे हैं, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। ठेला चालकों, छोटे दुकानदारों और किराए पर रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि वह बड़े सिलिंडर का खर्च नहीं उठा सकते। मजबूरी में उन्हें महंगे विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं।

अब बंगाल में भी जंगलराज की गूंज, मालदा कांड पर पीएम मोदी ने किया वार, टीएमसी ने ऐसे किया पलटवार

मालदा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला. पीएम ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया. पीएम ने कहा कि बंगाल में जंगलराज है. वहीं तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी के आरोपों पर पलटवार किया. टीएमसी ने पीएम के आरोपों को पाखंड बताते हुए बीजेपी शासित राज्यों में अपराध के आंकड़े जारी कर दिए.

पीएम मोदी का वार- 4 मई के बाद होगा पाई-पाई का हिसाब

प्रधानमंत्री ने कूचबिहार की धरती से ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है. पीएम ने कहा, बंगाल की निर्मम सरकार हर रोज लोकतंत्र की हत्या कर रही है. मालदा में न्यायाधीशों को बंधक बनाया जाना इसका ताजा सबूत है. मालदा में जो हुआ वह तृणमूल कांग्रेस के महाजंगलराज का उदाहरण है. पीएम मोदी कहा कि 4 मई (चुनाव परिणाम के बाद) कानून अपना काम करेगा. अपराधी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा और न्याय सुनिश्चित होगा. पीएम मोदी के हिसाब वाले बयान पर टीएमसी ने पलटवार करते हुए लंबी फेहरिस्त जारी की और बीजेपी की वाशिंग मशीन नीति पर तंज कसा. टीएमसी ने पूछा, आप अपना हिसाब सुवेंदु अधिकारी से क्यों नहीं शुरू करते, जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे? उन 25 विपक्षी नेताओं का हिसाब क्या हुआ जो बीजेपी में जाते ही साफ-सुथरे हो गए? पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह और कुलदीप सेंगर जैसे नामों का जिक्र करते हुए पीएम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर माफी मांगने को कहा.

सुशासन और रोजगार पर छिड़ी रार

बीजेपी के सुशासन के दावों के जवाब में टीएमसी ने NCRB और बेरोजगारी के आंकड़े पेश किए. टीएमसी ने दावा किया है कि 2014 के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध 33% बढ़े हैं और यूपी में हर घंटे 8 मामले दर्ज होते हैं. पार्टी ने आरोप लगाया कि 15-25 साल के 40% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जबकि केंद्र में 10 लाख पद खाली पड़े हैं.

मुसलमानों नहीं, घुसपैठियों के खिलाफ है भाजपा, नितिन गडकरी को असम-बंगाल में पार्टी की जीत का भरोसा

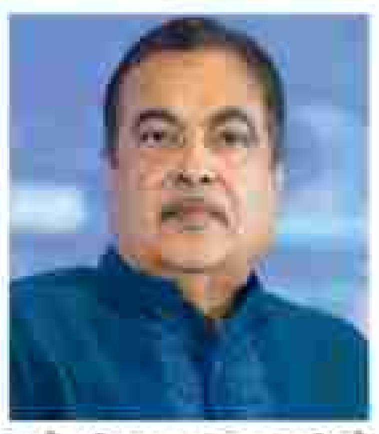

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि उनकी पार्टी मुसलमानों के नहीं, घुसपैठियों के खिलाफ है। इसी के साथ उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का भरोसा भी जताया। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा सभी को साथ लेकर चलने की नीति पर काम करती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने दोहराया कि पार्टी का विरोध केवल अवैध घुसपैठ के खिलाफ है। गडकरी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भाजपा असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में जीत हासिल करेगी। असम में नौ अप्रैल को मतदान होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग होगी। सभी पांच चुनावी राज्यों की मतगणना चार मई को होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की रणनीति का मुख्य आधार विकास और सुशासन है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में करीब पांच लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से बड़ी संख्या में काम पूरे हो चुके हैं और कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। गडकरी के मुताबिक सड़क, राजमार्ग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े ये प्रोजेक्ट क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारने, व्यापार बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति सभी को साथ लेकर चलने की है और पार्टी किसी भी जाति, धर्म या भाषा के खिलाफ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का रुख संविधान के अनुरूप अधिकार देने का है। हाल ही में असम में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत साझा विरासत वाले लोगों को शरण दे सकता है, लेकिन अवैध घुसपैठ को स्वीकार नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि वहां के लोगों में बदलाव की इच्छा बढ़ रही है और भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने माना कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी।

ट्रम्प ने ईरान को बास्टर्ड कहा- धमकी दी- होर्मुज खोलो, नहीं तो नरक बना दूंगा

तेल अवीव । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को बास्टर्ड कहते हुए होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज नहीं खोला तो वो उसे नरक बना देंगे।

इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही।

ट्रम्प ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा यानी हमला होगा। ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोले दे, नहीं तो नरक जैसे हालात में पहुंच जाएगा। अमेरिका ने इससे पहले गुरुवार को ईरान की राजधानी तेहरान को करज शहर से जोड़ने वाले B1 हाईवे ब्रिज पर हमला किया था। यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग 400 मिलियन डॉलर (करीब 3,800 करोड़) खर्च हुए थे।

ईरान ने ट्रम्प का 48 घंटे का अल्टीमेटम ठुकराया

ईरान ने ट्रम्प के 48 घंटे में होर्मुज खोलने के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका बेबस और घबराकर धमकियां दे रहा है। ट्रम्प ने ईरान को होर्मुज खोलने या समझौता करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि समय खत्म हो रहा है और ऐसा नहीं होने पर ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा।

रूस बोला- अमेरिका को अल्टीमेटम की बजाय बातचीत करनी चाहिए

रूस ने अमेरिका से अल्टीमेटम की भाषा छोड़कर बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील की है। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत में यह बात कही।

लावरोव ने उम्मीद जताई कि युद्ध को कम करने की कोशिशें सफल होंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर अल्टीमेटम देने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाए, तो हालात सामान्य हो सकते हैं। रूस और ईरान दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे किसी भी कदम से बचना चाहिए, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जो कूटनीतिक समाधान की बची हुई संभावनाओं को कमजोर कर सकता है। दोनों देशों ने माना कि मौजूदा संकट का हल राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है और इसके लिए तनाव कम करना जरूरी है।

हिमंता बिस्व सरमा को नहीं बख्शेंगे, सत्ता में आते ही भेजेंगे जेल, असम सीएम को राहुल गांधी की चेतावनी

बिस्वनाथ । असम के बिस्वनाथ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर कड़ा हमला किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज्य की राजनीति में बाहरी दखल का आरोप लगाते हुए कहा कि असम की कमान असल में दिल्ली के हाथों में है। उन्होंने भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले समय में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर संघर्ष और तेज करेगी। असम की रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करते हैं और नरेंद्र मोदी व अमित शाह आपके मुख्यमंत्री को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असम की सरकार को मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि दिल्ली से अमित शाह चला रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार को भ्रष्टाचार में शामिल करके बड़ी गलती की है। अब उनके परिवार को भी आरोपों का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस सत्ता में आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा को माफी मांगने पर भी नहीं छोड़ेंगे और जेल भेजकर दम लेंगे। चुनावी सभा के साथ-साथ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी केंद्र सरकार के वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए ये केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि मोदी सरकार इस मामले में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है।

उन्होंने सुरक्षा को सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि पीड़ित महिलाएं मदद के लिए भटक रही हैं लेकिन सरकार ने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में भी वन स्टॉप सेंटर की बदहाली का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूछा था कि इन सेंटरों में ताले क्यों लगे हैं और वहां स्टाफ की कमी क्यों है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार से सवाल किया कि आखिर पांच में से तीन महिलाओं तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही है। राहुल ने बजट के कम इस्तेमाल और देशभर से आ रही शिकायतों पर सरकार की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार से पिछले पांच वर्षों में खुले नए सेंटरों और वहां खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा।

यूपी में प्रीपेड पीड़ित, बिजली के स्मार्ट मीटरों की समस्या पर बोले अखिलेश यादव

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले सूबे की सियासत गरमाने लगी है, पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है. अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के कहर की वजह से उप्र में पीड़ित लोगों की एक नई श्रेणी बन गई है, जिसका नाम 'प्रीपेड पीड़ित' है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- बीजेपी सरकार के कहर की वजह से उप्र में पीड़ित लोगों की एक नई श्रेणी बन गई है, जिसका नाम है 'प्रीपेड पीड़ित'. 'प्रीपेड पीड़ित' का मतलब ये है कि जो लोग बिजली के प्रीपेड मीटर लगाकर बैठे हैं वो स्मार्ट मीटर की खामियों की वजह से बिजली कट जाने पर अंधेरे और गर्मी का संकट झेलने को मजबूर हैं.

दर-दर भटकने को मजबूर है जनता- अखिलेश

सपा चीफ ने आगे लिखा-जब बिजली खाते में बिजली के इस्तेमाल करने से पहले ही पैसा जमा हो जाता है तो फिर सरकार और कंपनी जनता को क्यों परेशान कर रही है. बिजली कंपनियों को तो पैसा पहले ही मिल जाता है, फिर उन्हें आम जनता की चिंता करने की क्या पड़ी है. बेचारी जनता दर-दर भटकने पर मजबूर है लेकिन सरकार और कंपनियों के सामने कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि वो पहले से ही मिलीभगत करके पैसे कमा के बैठे हैं.

उपभोक्ता नहीं, उपभुगता रह गई जनता- अखिलेश यादव

उन्होंने कहा सच तो ये है कि बीजेपी राज में अब जनता 'उपभोक्ता' नहीं रह गई है, 'उपभुगता' हो गई है क्योंकि वो हेराफेरी से बनी बीजेपी सरकार के दुष्परिणामों को 'भुगतने' पर मजबूर है.

इसी कारण पीडीए की संख्या भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं और आज भी कह रहे हैं जो पीड़ित, वो पीडीए! अब पीडीए में जुड़े ये नये 'प्रीपेड पीड़ित' कह रहे हैं कि चिंता न करें बुरे दिन जानेवाले हैं. पीड़ित सरकार आएगी, सबको बिजली दिलवाएगी।

कबाड़ चोरी करने गए 3 लोगों की जहरीली गैस से मौत

रांची । झारखंड के धनबाद जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां गैस लीक होने से तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह घटना कथित तौर पर कबाड़ चोरी के दौरान हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना धनबाद के मुनीडीह इलाके में रविवार तड़के करीब 1 बजे हुई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मुनीडीह थाना प्रभारी मणिका तिवारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ लोग लोहे का कबाड़ चोरी करने के लिए वहां पहुंचे थे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक भरे हुए गैस सिलेंडर को काट दिया, जिससे गैस लीक होने लगी। गैस की गंध इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोग बेहोश हो गए। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक दिनेश कुमार गिंदोरिया ने बताया कि कुल पांच लोगों को अस्पताल लाया गया था। उन्होंने कहा कि दो लोगों को मृत अवस्था में लाया गया, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सभी पहलुओं को खंगालने में जुटी है।

बीजेपी-चुनाव आयोग पर भड़कीं ममता- ईवीएम बदलने की जताई आशंका, कहा- अगर मशीन खराब हो तो बदलवाओ

कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को चुनावी सभा में मतदाताओं से अपील की कि वे वोट के जरिए बदला लेने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने भवानीपुर में एक रैली में अपनी कार्यकर्ताओं से ईवीएम की निगरानी करने के लिए कहा है। रविवार को समसेरगंज में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि जिन लोगों के नाम सूची से हटे हैं, वे ट्रिब्यूनल में अपील करें और मतदान के जरिए इसका जवाब दें। उन्होंने कहा, ऐसा वोट करें कि नतीजे ही बता दें कि नाम हटाने की राजनीति स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में मतदाताओं के नाम हटाने के पीछे उनकी भूमिका है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो सीधे मुकाबला करें।

चुनावी सतर्कता और ईवीएम पर बयान

मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 4 मई तक पूरी सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि कुछ जगहों पर ईवीएम मशीनें खराब कराई जा सकती हैं। ऐसे में उन्होंने निर्देश दिया कि मशीनों को मरम्मत न होने दें, बल्कि उन्हें बदलने की मांग करें। ममता बनर्जी ने कहा, «सभी ईवीएम मशीनों की अच्छे तरह से जांच करें। बूथ एजेंटों को भी ईवीएम की अच्छे तरह से जांच करनी चाहिए... मुझे उनकी योजना पता है... वोटिंग के बाद, सीआरपीएफ और केंद्रीय बलों की निगरानी में, वे अंदर जाकर मशीन बदल सकते हैं, इसलिए हमें 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। आपको ध्यान से देखना होगा कि वे ईवीएम को हैक न कर लें।

वक्फ कानून और हिंसा का जिक्र

मुर्शिदाबाद जिले के समसेरगंज, जो 2025 में वक्फ बिल के विरोध में हिंसा का केंद्र रहा था, वहां ममता ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा की है। उन्होंने भाजपा पर उनके खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया।

चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर कुछ लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और कुछ को डराया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव वाली मतदाता सूची से ही विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते थे। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उनकी सरकार एनआरसी के नाम पर किसी भी तरह के डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से उनके खिलाफ बदले की राजनीति की जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।

बागेश्वर जिले में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता

बागेश्वर । उत्तराखंड के बागेश्वर में रविवार की सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह 11 बजकर 47 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र कपकोट तहसील के कर्मी गांव के समीप जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। हालांकि झटके सामान्य होने के कारण जनजीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। भूकंप के झटके इतने सामान्य थे कि अधिकतर लोगों को इसका अहसास तक नहीं हुआ। जिले में कहीं भी अफरा-तफरी की स्थिति देखने को नहीं मिली। जिला मुख्यालय सहित गरुड़, कपकोट और कांडा क्षेत्रों में स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी रही।

10 अप्रैल तक जारी रहेगा बारिश और बिजली का दौर

नई दिल्ली । उत्तर भारत के मौसम ने अचानक करवट ले ली है. जिसके कारण हालात ऐसे है कि अप्रैल महीने के दौरान भी कहीं- कहीं दिसंबर जैसी ठंड के एहसास से बक्से में बंद होने जा रही रजाइयों को फिर से निकालने के लिए मजबूर कर दिया है. मौसम केंद्र ने आने वाले हफ्ते में दो पश्चिमी विक्षोभ के देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को प्रभावित करने की चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार, 7 और 8 अप्रैल को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर , लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली में सबसे ज्यादा असर दिखने की उम्मीद है.

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में ओले

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आगामी सप्ताह में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है उत्तर-पश्चिम भारत में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे है. जिसके चलते 7 अप्रैल को कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है. इस दौरान 30-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. एक भयंकर पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, पश्चिम यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में 7-9 अप्रैल से बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि लाने को तैयार है! यह शक्तिशाली सिस्टम भारत के 30-40 फीसदी क्षेत्र को प्रभावित करेगा।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश तो राजस्थान में चलेगी धूल भरी आंधी

वहीं 7 और 8 अप्रैल को इन राज्यों सहित दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. दिल्ली में 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, दिल्ली में आंधी -तूफान के दौर के साथ ही अगले 24 घंटे को दौरान राजस्थान में भी 6 और 7 अप्रैल को राज्य में 50-70 किमी/घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है.

बिहार-झारखंड में आंधी-तूफान का अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत में बर्फबारी, मैदानों में ओले के अलर्ट के बाद देश के पूर्वी हिस्सों में भी बिगड़े मौसम के मिजाज का ही अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने इन हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिसके चलते 6 से 8 अप्रैल के बीच बिहार और झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ 70 किमी घंटे की रफ्तार से तूफानी आंधी चलने की संभावना है. इसके साथ ही 8 और 9 अप्रैल को सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा का अनुमान है.

मध्य और दक्षिण भारत का हाल

उत्तर-पश्चिम, पूर्वी हिस्सों की तरह ही मध्य और दक्षिण की स्थिति भी एक समान है. मौसम विभाग ने 5 से 8 अप्रैल के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई है. वहीं तमिलनाडु, केरलम और तटीय आंध्र प्रदेश में 5 और 6 अप्रैल को छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है.

7 से 10 अप्रैल तक जारी रहेगा बारिश, गरज और ओलावृष्टि का दौर

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, 7 से 10 अप्रैल के बीच मैदानी इलाकों में तेज बारिश, गरज और ओलावृष्टि का दौर जारी रह सकता है. हालांकि 8 से 10 अप्रैल के बाद यह सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और एक बार फिर गर्मी तेजी से लौटेगी. अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा सूखा और ज्यादा गर्म रहने का अनुमान है.